

उपमुख्यमंत्री ने पर्यटन स्थलों के लिए वीआर शो की रूपरेखा तैयार करने के दिये निर्देश

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के दिए निर्देश

जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में सोमवार को प्रमुख शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव, पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाड़ की उपस्थिति में शासन सचिवालय में पर्यटन विभाग एवं कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग से जुड़े विभिन्न विकास कार्यो एवं योजनाओं तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन और कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग से जुड़े विभिन्न विकास कार्यो एवं योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए साथ ही समय बढ़ता से लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्देश दिए।

दिया कुमारी ने महाराणा प्रताप ट्ययूरिस्ट सिक्रिट, शेखावाटी हवेलियों, ट्राईबल सिक्रिट, जवाहर कला केंद्र, शिल्पग्राम जैसे विकास कार्यो पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समीक्षा बैठक में पर्यटन विभाग के मार्केटिंग शाखा द्वारा एआर/वीआर शो की रूपरेखा के संबंध में चर्चा की।



उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रमुख शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव, पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाड़ की उपस्थिति में शासन सचिवालय में बैठक ली।

उन्होंने महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए एआर/वीआर शो की रूपरेखा तैयार करने के भी निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री ने उक्त समीक्षा बैठक में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा झुन्झुनू में बनवाये जाने वाले वार म्युजियम की चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। इसी प्रकार उप मुख्यमंत्री को ट्ययूरिज्म ऐप हेतु जानकारी दी गई कि इस हेतु बोली की तैयारी

प्रक्रियाधीन है। दिया कुमारी को पर्यटन विभाग की विकास शाखा/टीआरसी जयपुर की ओर से जेडीए को जयपुर में कॉन्स्टर्ट पर्यटन के विकास हेतु पूर्व में आरक्षित भूमि को आवंटित करने का अनुरोध करने की जानकारी दी गई। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी को समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि होटो के लिए जेसीटीएसएल द्वारा की जा रही

कार्यवाही से अवगत कराया गया। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि नगर निगम जयपुर द्वारा जयपुर वाल्ड सिटी वर्क तकनीकी बोलियों अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार ए एण्ड एम द्वारा अलबर्ट हाल वर्क हेतु प्राप्त ई-निविदाएँ समीक्षा प्रक्रिया में है। आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले आमेर मास्टरप्लान पर भी चर्चा की गई।

अनिल मलिक ने चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर का किया निरीक्षण

जयपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव अनिल मलिक ने जयपुर के रामनगरिया स्थित आननबाड़ी केंद्र, जयपुरिया अस्पताल में परिसर में स्थित वन स्टॉप सेंटर और मानसरोवर में बाल अधिकारिता विभाग के तहत संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर का निरीक्षण किया। मलिक ने निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत : डॉ. किरोड़ी लाल

जयपुर। राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और आम नागरिकों के लिए बड़ा राहत पैकेज जारी किया है। वे मौसम बारिश, अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान की समीक्षा के बाद सरकार ने 43 लाख 39 हजार किसानों को 2,600 करोड़ रुपये के कृषि आदान-अनुदान वितरण का निर्णय लिया है।

आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि वर्ष 2025 में हुई बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रदेश के 30 जिलों में 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल खराब हुई है, जबकि 11 जिलों में फसल नुकसान 33 प्रतिशत से कम आंका गया है। विभागीय अधिसूचना के अनुसार 24 जिलों के 14,687 गांवों के कुल 43 लाख 39 हजार किसान प्रभावित हुए हैं, जिन्हें एसडीआरएफ नियमों के तहत राहत राशि वितरित की जाएगी।

मंत्री ने बताया कि असामान्य बारिश के कारण प्रदेश में सार्वजनिक परिसंपत्तियों को भी गंभीर क्षित पहुंची है। इसके पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए सरकार ने 50,3०8 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है, जिन पर 1,012

- सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और आम नागरिकों के लिए बड़ा राहत पैकेज जारी किया**
- बारिश और आपदाओं के कारण हुई 112 जनहानि में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई**

करोड़ 61 लाख रुपये की राशि मंजूर की जा चुकी है। इनमें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत के 14,212 कार्यों पर 293 करोड़ 13 लाख रुपये तथा पुलिसा मरम्मत के 1,161 कार्यों पर 7 करोड़ 20 लाख रुपये का व्यय स्वीकृत किया गया है। जल संसाधन विभाग के 903 कार्यों के लिए 18 करोड़ 67 लाख रुपये, चिकित्सा विभाग के 700 कार्यों के लिए 13 करोड़ 18 लाख रुपये, पंचायती राज विभाग के 873 कार्यों के लिए 19 करोड़ 39 लाख रुपये, पीएचईडी के 17 कार्यों के लिए 22 लाख 69 हजार रुपये तथा शिक्षा विभाग के 24,531 कार्यों पर 486 करोड़ 94 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। महिला एवं बाल

विकास विभाग के लिए 173 करोड़ 03 लाख रुपये अनुमोदित किए गए हैं।

बारिश और आपदाओं के कारण हुई 112 जनहानि में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 4 करोड़ 48 लाख रुपये जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं के नुकसान, घर के सामान, कपड़ों तथा मकानों की मरम्मत हेतु 11 करोड़ 54 लाख रुपये की सहायता भी उपलब्ध कराई गई है।

राज्य सरकार ने कहा है कि वह प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हर नागरिक के साथ खड़ी है और त्वरित राहत, पारदर्शिता तथा पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

सरदार पटेल यूनिटी मार्च में देशभक्ति और एकता का संदेश दिया

जयपुर/सवाई माधोपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल के नेतृत्व में सोमवार को चौथ का बरवाड़ा में भव्य सरदार पटेल यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। गुडला वाले हनुमान जी मंदिर से प्रारंभ होकर चौथ का बरवाड़ा ट्रस्ट की धर्मशाला तक निकाले गए इस ऐतिहासिक मार्च ने पूरे क्षेत्र में उत्साह,

- भाजपा महामंत्री एवं खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने जनसमूह को संबोधित किया**



चौथ का बरवाड़ा में भव्य सरदार पटेल यूनिटी मार्च का आयोजन किया ।

समाजों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने पुष्प वर्षा कर कार्यकर्ताओं और कलाकारों का मनोबल बढ़ाया। युवा, बुजुर्ग, महिलाएँ सहित बड़ी संख्या के श्रववासी मार्च में लगातार जुड़ते गए, जिससे इसका स्वरूप और अधिक विशाल व ऐतिहासिक बन गया।

भाजपा महामंत्री एवं खंडार

विधायक जितेंद्र गोठवाल ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल केवल एक नाम नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और दृढ़ नेतृत्व के प्रतीक हैं। उनकी संलग्नता गुर्जर, और राष्ट्रनिर्माण की दूरदर्शिता नवभारत की मजबूत नींव है। उनका जीवन हमें कर्तव्य, अनुशासन और राष्ट्रसेवा की

प्रेरणा देता है। इस यूनिटी मार्च के माध्यम से क्षेत्रवासियों ने एक स्वर में संदेश दिया एक भारत, श्रेष्ठ भारत, केवल नारा नहीं, हमारा संकल्प है। यूनिटी मार्च में भाजपा जिला अध्यक्ष मानसिंह गुर्जर, मंडल पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई।

विद्युत विभाग का लाईन मैन अपने दलाल साथी सहित रिश्तत लेते गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की भिवाड़ी टीम ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम मुबारिकपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर के लाइनमैन द्वितीय दिनेश कुमार और प्राइवेट व्यक्ति राजकुमार को पांच हजार रुपये की रिश्तत लेते गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी की भिवाड़ी टीम को परिवादी ने शिकायत दी कि उसके पिताजी के नाम करीब 3 वर्ष पूर्व फेस कृषि कनेक्शन की पत्रावली सहायक अभियंता जेवीवीएनएल रामगढ़ जिला अलवर में लगाई थी। जिसका डिमांड

- लाइनमैन द्वितीय दिनेश कुमार और प्राइवेट व्यक्ति राजकुमार को पांच हजार रुपये की रिश्तत लेते गिरफ्तार किया**
- शिकायत मिलने पर एसीबी ने गोपनीय सत्यापन करवाया गया**

नोटिस करीब 10 माह पूर्व उक्त कार्यालय द्वारा जारी किया गया तो उसके द्वारा डिमांड नोटिस राशि जमा करवाई गई।

इस कनेक्शन के पेटे ट्रांसफार्मर की इण्डेन कटवा कर ट्रांसफार्मर देने की एतज में लाइनमैन द्वितीय दिनेश कुमार दिनेश कुमार और दलाल राजकुमार को पांच हजार रुपये की रिश्तत लेते गिरफ्तार किया गया है।

की रिश्तत की मांग की जा रही है। शिकायत मिलने पर एसीबी ने गोपनीय सत्यापन करवाया गया। एसीबी आीम भिवाड़ी के उप अधीक्षक पुलिस परमेश्वर लाल के नेतृत्व में ट्रेप की कार्रवाई करते हुए लाईन मैन द्वितीय दिनेश कुमार और दलाल राजकुमार को पांच हजार रुपये की रिश्तत लेते गिरफ्तार किया गया है।

भगवती पेपर मिल में लगी भीषण आग

जयपुर। जयपुर ग्रामीण जिले के कालाडेरा थाना इलाके में स्थित रीको एरिए में एक पेपर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लाखों रुपए का माल आग की भेंट चढ़ गया। सूचना पर आठ अलग-अलग जगहों की दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के आग आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टि आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

पुलिस ने बताया कि कालाडेरा रीको औद्योगिक क्षेत्र में रविवार देर रात भगवती पेपर मील में अचानक से आग लग गई थी। जिसमें लाखों रुपए का कच्चा पेपर आग की भेंट चढ़ गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी अग्निशमन अधिकारी को दी।

मौके पर पहुंचे अग्निशमन अधिकारी जय कुमार जांगिड़ ने बताया कि मौके पर पहुंचने से आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। जिसे काबू में करने के लिए चोर्म्, जयपुर, कालाडेरा, सरना ड्यूरी, जोलेनर ,रेनवाल, रींगसे और मंडा सहित आठ अलग –अलग जगहों से फायर ब्रेड्रेड की गाड़ियों को बुलाया गया। दमकल विभाग की आठ गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टि से आग का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया।

विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत

जयपुर। विद्याघर नगर थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों एक विवाहिता की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कांवटिया अस्पताल के मुर्दाघर में भिजवाया। जहां से उसका पोस्टमार्टम करवा शव शनिवार को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

वहीं इस मामले को लेकर मृतका की माँ ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। थानाधिकारी नरेंद्र खीचड़ ने बताया कि विवाहिता ज्योति पत्नी महेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद इलाके की रहने वाली थी। इसके पहले पति से इसका तलाक हो चुका था और 4 महीने पहले महेंद्र से इसकी शादी हुई थी।मृतका की मां लीला देवी ने मामला दर्ज कराया है कि शादी के बाद से ज्योति के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। महेंद्र सिंह, हरफूल जाट ,बजरंग जाट और शंकर जाट के साथ मिलकर उसकी बेटी को 14 नवंबर को गला घोट के मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को ज्योति के गले पर चोट के निशान मिले है।

रनिंग कर्मचारियों के मुद्दों पर निर्णय नहीं लिए जाने पर विरोध-प्रदर्शन किया

जयपुर। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आब्धान पर नार्थ वेस्टर्न रेलवे एम्पलाइज यूनियन महामंत्री मुकेश माथुर के निर्देश पर नार्थ वेस्टर्न रेलवे एंप्लॉयीज यूनियन के बैनर तले सोमवार को उत्तर पश्चिम रेलवे स्थित विभिन्न रनिंग लॉबी पर रेलवे बोर्ड द्वारा रनिंग कर्मचारियों के मुद्दों पर निर्णय नहीं

- जोनल प्रशासन द्वारा मनमर्जी से कार्यवाही करने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया**

लिए जाने एवं जोनल प्रशासन द्वारा मनमर्जी से कार्यवाही करने के विरुद्ध में लोको पायलट एवं गाड़ी प्रबंधक संयुक्त लॉबी जयपुर पर मंडल अध्यक्ष के एस अहलावत, मंडल मंत्री राकेश यादव एजीएस गोपाल मीना की अगुआई में रेल कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है।

यूनियन के सहायक मण्डल मंत्री अनूप कुमार शर्मा ने बताया कि आल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन की कोलकाता में विगत दिनों सम्पन्न कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार यह प्रदर्शन पूरे देश में किया गया। उन्होंने बताया कि महंगाई भते के



मंडल अध्यक्ष के एस अहलावत, मंडल मंत्री राकेश यादव एजीएस गोपाल मीना की अगुआई में रेल कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया ।

50 हो जाने पर 25 की दर से सभी भत्तों में वृद्धि कर दी गई है, लेकिन रनिंग कर्मचारियों के किलोमीटर भत्ते में अभी तक वृद्धि नहीं हुई है। इसी प्रकार किलोमीटर भत्ते के 70 भाग को आयकर से मुक्त करने का निर्णय अभी तक सरकार ने नहीं लिया है।

उत्तर पश्चिम रेलवे पर मनमर्जी से कू वार्किंग में बदलाव किया जा रहा है, और रेवाड़ी लॉबी और जयपुर मण्डल

के गाड़ी प्रबंधकों एवम लोको पायलटों सहायक लोको पायलटों समेत रनिंग स्टाफ का तबादला किया जा रहा है जबकि लोको पायलट (मालगाड़ी) के पदों पर प्रधान कार्यालय के निर्देशों के बावजूद पदोन्नित नहीं हो रही है, एकरफर निर्णय करके नई लॉबी खोली जा रही है एवं कैडर रिय्यू इस वर्ष का अभी तक जारी नहीं किया गया है। इन सभी मुद्दों पर लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर,

डिजिटाइजेशन में राजस्थान सभी राज्यों में अग्रणी

जयपुर। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम–2०26 के अंतर्गत गणना प्रपत्र वितरण, सत्यापन तथा डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरे राज्य में सक्रिय रूप से चल रही है। इस अभियान में बूथ लेवल अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पिछले 14 दिनों में घर–घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए हैं तथा उन्हें इस बात की विस्तृत जानकारी दी है कि प्रपत्र कैसे भरा जाए और किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन की गति लगातार बढ़ रही है और अब तक 1.65 करोड़ गणना प्रपत्र ईसीआईनेट पर अपलोड किए जा चुके हैं। जिन 12 राज्यों में फेज टू का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है।

छात्रों में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के लिए आईस्टार्ट कार्यक्रम संचालित

- 7100 से अधिक स्टार्टअप को मिला 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश**

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नवीन उद्यमों को बढ़ावा मिलने से राजस्थान में रोजगार का सृजन और निवेश में वृद्धि हो रही है। शर्मा के निर्देशन में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईस्टार्ट कार्यक्रम संचालित कर रहा है। इसके तहत आईस्टार्ट राजस्थान (एकीकृत स्टार्टअप प्लेटफॉर्म) के माध्यम से प्रदेश में स्टार्टअप को सुविधाएं और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा आईस्टार्ट पोर्टल प्लेटफॉर्म का संचालन और प्रबंधन किया जा रहा है, जिससे यह देश के बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन गया है। इसके साथ 7100 से अधिक स्टार्टअप जुड़े हुए हैं, जिन्हें 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश मिल चुका है, जिससे प्रदेश में 42 हजार 500 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। स्टार्टअप को मान्यता, उन्नयन, कोशल विकास, प्रोत्साहन, फंडिंग आईस्टार्ट प्लेटफॉर्म से मिल रही है। स्टार्टअप्स से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल बनाया गया है।

आईस्टार्ट पोर्टल सभी प्रोत्साहनों के लिए वन-स्टॉप गेटवे के रूप में कार्य कर रहा है। आईस्टार्ट कार्यक्रम के तहत सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप, मेंटर्स, छात्रों, शिक्षकों, व्याख्याताओं, स्कूलों, प्रशासकों आदि के लिए पोर्टल पर डैशबोर्ड बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टार्टअप को विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं।

क्यूरेट प्रोग्राम देश का एकमात्र स्टार्टअप रेटिंग तंत्र है। इसमें स्टार्टअप का मूल्यांकन कर परीक्षण किया जाता है और उन्हें वित्तीय सहायता और इनक्यूबेशन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके जरिए स्टार्टअप की निवेश क्षमता पर भी विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाती है और स्टार्टअप संस्थापकों को उनके उत्पाद, रणनीति, व्यावसायिक योजनाओं और बाजार को बेहतर बनाने, कमियों व सीमाओं पर काम करने के लिए बूट कैप आयोजित किए जाते हैं।

इनक्यूबेशन प्रोग्राम से मुफ्त स्थान, कनेक्टिविटी, कंप्यूटर हार्डवेयर, बुनियादी ढांचा, मेंटरशिप, बाजार से संपर्क, वीसी और निवेशक संपर्क, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व

विशेषज्ञों से संपर्क की सुविधा मिलती है। आईस्टार्ट नेस्ट निवेशकों और सलाहकारों का नेटवर्क है, जो स्टार्टअप को आगे बढ़ाने और नवाचारों को विकसित करने में मदद करता है। इस प्रोग्राम के जयपुर में इनक्यूबेशन सेंटर, टेक्नोहब और भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, पाली और चूरू में आईस्टार्ट नेस्ट इनक्यूबेटर हैं। सभी इनक्यूबेशन सेंटरों में स्टार्टअप के लिए 2०00 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं।

टेक्नो हब देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है, इसमें 7०0 से ज्यादा स्टार्टअप के लिए स्थान है और 1 लाख 50 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता है। टेक्नो हब स्टार्टअप के लिए एक वन-स्टॉप समाधान है। इनक्यूबेशन सेंटर की सुविधा संभाग स्तर पर भी उपलब्ध है।

राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप को आइडिया व प्रोटोटाइप चरण में 2 लाख 40 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता (महिला स्टार्टअप के लिए 3 लाख रुपये) दी जाती है। इसी प्रकार, सीड चरण में 60 लाख रुपये तक और ऋण के रूप में 2 करोड़ रुपये तक वित्तीय सहायता और इक्विटी के रूप में 5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।